इकाई 11 क्रान्तिकारी आन्दोलन और सामाजिक बदलाव

इकाई की रूपरेखा

11.1 प्रस्तावना

11.2 क्रान्ति की प्रक्रिया

11.2.1 सामाजिक बदलाव का अंग

11.2.2 क्रान्ति के कारण

11.3 सफल क्रान्तियाँ

11.3.1 मैक्सिको की क्रान्ति

11.3.2 बोलाविया की क्रान्ति (1952-1964)

11.3.3 क्यूबा की क्रान्ति

11.3.4 निकारागुआ की क्रान्ति

11.4 तुलनात्मक विश्लेषण

11.5 सारांश

11.6 अभ्यास प्रश्न

11.1 प्रस्तावना

क्रान्तिकारी आन्दोलन उन आमूल परिवर्तनों के संदेशवाहक होते हैं जो केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी होते हैं। लैटिन अमेरिका में क्रान्ति को अक्सर बहुत अलग ढंग से परिभाषित किया जाता है। वहाँ इसे हिंसा, सामाजिक बदलाव अथवा शासन में बदलाव के अर्थ में लिया जाता है और यहाँ तक कि तानाशाही सैनिक शासन के संदर्भ में भी क्रान्ति शब्द का प्रयोग किया गया है। बीसवीं शताब्दी की ऐसी चार स्पष्ट क्रान्तियाँ हैं जिन्हें सफल कहा जा सकता है – मैक्सिको की क्रान्ति (1910), बोलाविया की क्रान्ति (1952), क्यूबा की क्रान्ति (1959) और निकारागुआ की क्रान्ति (1979)। किन्तु, लैटिन अमेरिका की अनेक क्रान्तियों के व्यापक फलक में इनको अत्यधिक दुर्लभ अथवा अनूठा माना जाता है। क्योंकि इन क्रान्तियों ने केवल इन देशों और लैटिन अमेरिकी क्षेत्र के भीतर ही नहीं बल्कि उस गोलार्द्ध में आपसी रिश्तों और विश्व की राजनीति पर भी जबरदस्त प्रभाव डाला है। इन क्रान्तियों से जुड़े सामाजिक बदलाव को समझने के लिए लैटिन अमेरिकी क्रान्तियों के कारणों, प्रक्रिया और परिणामों की विवेचना करना, और विशेषकर लैटिन अमेरिकी क्रान्तियों की विशिष्टताओं को रेखांकित करना आवश्यक है। इन चार सफल क्रान्तियों के अतिरिक्त, लैटिन अमेरिका में अन्य क्रान्तिकारी आन्दोलन भी हुए हैं जिन्हें सफल नहीं माना जाता है। जैसे एल सल्वाडोर का फाराबुंडो मार्टी राष्ट्रीय मुक्ति (Farabundo Marti National Liberation – FMLN) आन्दोलन और पेरू का '*सेंडरो लूमीनोसो*' ("चमकदार पथ") आन्दोलन। इस इकाई में आपको संक्षेप में यह बताया जाएगा कि लैटिन अमेरिका में कितनी और कैसी क्रान्तियाँ हुईं। यहाँ ऐसे आन्दोलनों की समानताओं और विशिष्टताओं को भी रेखांकित किया जाएगा।

11.2 क्रान्ति की प्रक्रिया

11.2.1 सामाजिक बदलाव का अंग

सामाजिक बदलाव में योगदान करने वाले अनेक कारक "सामाजिक गतिशीलता" की श्रेणी में आते हैं,

अर्थात् शहरीकरण, शिक्षा, जन संचार और बढ़ती अपेक्षाएँ। एक कारक है अन्य समाजों से लिए गए नए विचार (जैसे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ का उदारवाद और बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ का मार्क्सवाद) अथवा जीत-पूर्व काल से पुनः प्रवर्तित विचार (जैसे मैक्सिको का 'इंडिजेनिस्मो' अथवा स्थानिकवाद और निकारागुआ का 'सैंडिनिस्मो')। इनसे छिटपुट और बिखरे हुए सामाजिक असंतोष को दिशा मिलती है।

सामाजिक बदलाव में योगदान करने वाला एक और कारक है सामाजिक बदलाव के साधक। चाहे वे नई महत्वाकांक्षाओं वाले विदेशी हों अथवा नई संस्थाओं या नई भूमिका निभाने वाली पुरानी संस्थाओं से जुड़े लैटिन अमेरिकी लोग। मुक्ति के धर्मशास्त्र से प्रेरित कैथोलिक पादरी और छात्रों को भी इसका उदाहरण माना जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं, युद्ध अथवा किसी मामूली घटना या विरोध पर सत्ताधारी वर्ग की प्रतिक्रिया पर भी बदलाव के लिए दबाव बनाया जा सकता है।

यदि राजनीतिक कुलीन सत्ता में भागीदारी करने और नए समूहों को शामिल करने में सक्षम होते हैं तो सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया स्वाभाविक ढंग से शुरू होती है। किन्तु, यदि कुलीन वर्ग भागीदारी नहीं करना चाहता और बदलावों को दबाने का प्रयास करता है, तो वे क्रान्ति अथवा प्रति क्रान्ति का रूप ले सकते हैं। क्रान्ति के फलस्वरूप पिछली व्यवस्था और उस व्यवस्था में भागीदारी करने वाले तो विस्थापित नहीं होते, किन्तु क्रान्ति में समाज के उच्च वर्गों का विस्थापन अवश्य हो जाता है अथवा वे व्यवस्था से हटा दिए जाते हैं। प्रति क्रान्ति में, समाज के निचले स्तर के समूहों को सत्ता की राजनीति में प्रभावी भागीदारी से अलग कर दिया जाता है।

लैटिन अमेरिका के मामले में, नए समूहों को अर्जेन्टीना, चिली और उरूग्वे के दक्षिणी देशों के राज्यतंत्र में शामिल करने के लिए किसी बहुत बड़ी सामाजिक खाई को नहीं पाटना था। यह क्षेत्र सोना और चांदी से सम्पन्न नहीं था और इसीलिए उपनिवेशकों के हाथों उसके शोषण की इतनी संभावना नहीं थी। इसलिए यूरोपीय लोग यहाँ अपेक्षाकृत देरी से आकर बसे, और यहीं सबसे पहले आज़ादी भी आई। आज़ादी के समय यहाँ की आबादी अधिकतर 'मैस्तीज़ो' की और एकरूप थी। यहाँ मज़दूर वर्ग की भागीदारी और पर्याप्त पुनर्वितरण का काम क्रान्ति की प्रक्रिया से हुआ। सशस्त्र बलों और वर्चस्वशाली विदेशी सत्ता के सहयोग से मध्यम वर्ग का समर्थन लेकर (विदेशी और स्थानीय) आर्थिक कुलीनों ने निम्न वर्गों की आवाज़ को दबा दिया। किन्तु, मैक्सिको, क्यूबा, निकारागुआ और बोलाविया जैसे देशों में क्रान्तिकारी बदलाव हिंसक टकराव के साथ आया।

11.2.2 क्रान्ति के कारण

हमने देखा कि क्रान्ति सामाजिक बदलाव का एक अंग है। किन्तु सामाजिक बदलाव अथवा गतिशीलता (लाभबंदी) अपने आपमें क्रान्ति का कारण नहीं बनती। हाँ, यह क्रान्ति के लिए बनने वाले दबावों में अवश्य योगदान करती है। क्रान्ति तभी होती है जब क्रान्तिकारी बदलाव की राह में रोड़े अटकाए जाते हैं। बदलाव में बाधा डालने वाले अनेक कारण अथवा कारक हैं।

इनमें एक महत्वपूर्ण कारक है राजनीतिक भागीदारी की कमी, जिसमें कुलीनों और जनसाधारण के बीच एक बड़ी सामाजिक खाई होती है। लैटिन अमेरिका में समाज की जो पारंपरिक सोपानिक परम्परा है और उसके साथ जो आर्थिक समस्याएँ हैं, उनके कारण हमेशा ही लोगों में असंतोष भड़का है। इस सामाजिक सोपानिक ढाँचे में यूरोपीय मूल के थोड़े से कुलीन हैं जिनकी विदेशी शक्तियों से निकटता है। सत्ता की पारंपरिक व्यवस्था में थोड़ा-सा बदलाव इनके लिए घातक हो सकता है। इसलिए इन्हें इस व्यवस्था में कोई भी बिगाड़ स्वीकार्य नहीं है। थोड़े बहुत बदलाव को स्वीकार करने और बिचौलिये की भूमिका निभाने में सक्षम मध्यम वर्ग के विकास का स्वागत करने के बजाय कुलीन

यथास्थिति और केन्द्र में निर्वात की स्थिति को बनाए रखने की कोशिश में रहते हैं। इससे यह सुनिश्चित हो जाता है कि उन्हें मध्यम अथवा निम्न वर्ग को कोई छूट नहीं देनी होगी।

यूरोपीय शक्तियों से स्वाधीन हो जाने के बाद भी, लैटिन अमेरिकी देशों पर विदेशी प्रभुत्व कायम रहा। स्वाधीनता का मतलब उनके लिए बस एक मालिक् के स्थान पर दूसरे मालिक का आना रहा। सत्ताधारी अभिजात्य वर्ग राष्ट्रीय प्रभुसत्ता की कीमत पर भी एक मज़बूत देश की थिगड़ी के नीचे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने को तत्पर था। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख निगम उन देशों के सत्ताधारी कुलीन वर्ग का एक अभिन्न अंग बन गए और संयुक्त राज्य अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए सैनिक हस्तक्षेप भी कर सकता है। इसका अर्थ यह होता था कि अपेक्षाकृत बहुत कम परिवारों के आर्थिक हितों की रक्षा होनी थी और बहुत कम का दांव राजनीतिक व्यवस्था में लगा था। इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका लैटिन अमेरिका में दबंग शक्ति के रूप में उभरा था।

एक और कारक लैटिन अमेरिका में किसानों और स्थानीय लोगों का विस्थापन था। स्थानीय लोगों को स्पेन के कुलीनों अथवा संयुक्त राज्य अमेरिका के निगमों ने उनके पारंपरिक स्थानों से हटा दिया था। इस तरह, ये लोग अपनी सामुदायिक जमीनों से वंचित हो गए थे। अधिकांश असंतोष का प्रत्यक्ष कारण परायेपन का भाव था।

इन सभी कारकों की परिणति शासक कुलीनों के खिलाफ एक बहु-वर्गीय गठबंधन में हुई। ऐसा विशेषकर क्यूबा और निकारागुआ में, और व्यापक तौर पर मैक्सिको ग्वाटेमाला और डोमिनिकन गणराज्य में हुआ। इस प्रकार, लैटिन अमेरिका की अधिकांश क्रान्तियों में एक समान बात यह रही कि ये किसानी प्रकृति के ऐसे बहु-वर्गीय जन-आन्दोलन थे जिनकी ऐसी कोई तय विचारधारा नहीं थी जिसे एक सामान्य कारक कहा जा सके।

11.3 सफल क्रान्तियाँ

11.3.1 मैक्सिको की क्रान्ति

उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मैक्सिको के राजनीतिक पटल पर, पोरफीरियो डियाज़ अथवा पोरफीरयाटो का 'कॉडिलो' शासन 1857 के संविधान का सिद्धान्तों का सिलसिलेवार उल्लंघन कर रहा था। डियाज़ का मानना था कि एक पिछड़े राष्ट्र को आधुनिक बनाने के लिए तानाशाही ज़रूरी थी। यह माना जाता था कि मैक्सिको का आर्थिक विकास विशेष अनुदान (सब्सिडी) और रियायतों के माध्यम से विदेशी मुद्रा खींचने पर निर्भर था। 1910 तक, अमेरिकी हितों के नियंत्रण में मैक्सिको की 75 प्रतिशत खानें, 72 प्रतिशत धातु उद्योग, 68 प्रतिशत रबड़ व्यापार और 58 प्रतिशत तेल-उत्पादन था। मैक्सिको के शेष उद्योगों के 80 प्रतिशत पर दूसरी विदेशी शक्तियों का नियंत्रण था। डियाज़ ने न केवल विदेशी हित समूहों को फुसलाया, बल्कि पादरियों को भी सांसारिक मामलों में खुले आम रौब जमाने की छूट दे दी और सेना को सुनिश्चित नागरिक स्वतंत्रताओं का उल्लंघन करने के लिए खुला छोड़ दिया। शासन के विरोधियों को या तो अपने साथ मिला लिया गया या फिर जेल भेज दिया गया।

एक 'हासेन्डाडो' के पुत्र, फ्रांसिस्को के इग्नासियो माडेरो, ने अक्टूबर 1910 में सान लूईस पोटोसी की योजना जारी की। इस योजना में राजनीतिक सुधारों, और लोकतांत्रिक सिद्धान्तों की बहाली की माँग की गई थी। योजना का उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ। जनवरी 1911 तक, चिवावा के उत्तरी राज्य में एक व्यापक विद्रोह फूट चुका था। इस विद्रोह का नेतृत्व एक स्थानीय व्यापारी पास्कुअल ओरोस्को

और फ्रांसिस्को "पाँचों" विला ने किया। सान लुईस पोटोसी की योजना में अपने आपको कामचलाऊ राष्ट्रपति घोषित कर चुका माडेरो इस नवजात क्रान्ति का नेतृत्व करने के लिए मैक्सिको लौट आया। चिवावा में विद्रोही जत्थों की सफलता देख पूरे देश में ऐसा ही विद्रोह फूट पड़ा। 1909 में मोरेलोस में, किसान नेता एमिलियानो-जपाटा ने हजारों बागान मज़दूरों और भूमिहीन किसानों को भर्ती करके बागानों पर हल्ला बोल दिया और खोई हुई जमीनों पर फिर से अपना दावा ठोंक दिया। 25 मई 1911 तक, पोरफीरियो डियाज़ ने इस्तीफा दे दिया और एक अन्तरिम सरकार को सत्ता सौंप दी।

माडेरो ने नवम्बर 1911 में राष्ट्रपति का पद संभाल लिया। नई सरकार के सामने अपार समस्याएँ थीं। डियाज़ के पतन ने लोगों में दूरगामी सामाजिक सुधारों विशेषकर भूमि सुधारों की अपेक्षा जमा दी थी। ज़पाटा भी मोरेलोस के किसानों के लिए बागानों की ज़मीन माँगने के उद्देश्य से मैक्सिको सिटी आ गया था। उसकी दृष्टि में डियाज़ का तख्ता पलटने का एकमात्र यही स्वीकार्य परिणाम हो सकता था। क्रान्तिकारियों के बीच भी, समाज के अलग-अलग वर्गों के लिए क्रान्ति का अलग-अलग अर्थ था। माडेरो की समझ में जल्दी ही यह बात आ गई कि उदारवादियों के लिए क्रान्ति का मतलब राजनीतिक बदलाव था, किन्तु क्रान्तिकारी सेनानियों के लिए इसका मतलब आमूल सामाजिक और आर्थिक बदलाव थे जिन्हें पूरा करना माडेरो के बस में नहीं था। इस तरह, मज़दूर अशान्ति चलती रही और ज़पाटा के समर्थकों तक ने विद्रोह कर दिया।

दूसरे क्षेत्र के क्रान्तिकारी नई सरकार को चुनौती देने लगे। इस बीच, पोरफीरियो के भतीजे (अथवा भानजे?) फेलिक्स डियाज़ और अन्य प्रति-क्रान्तिकारियों ने सैनिक तख्ता पलटने की साजिश रच डाली। शुरू में तो हुएर्ता के नेतृत्व वाली राजभक्त सेना की मदद से माडेरो ने डियाज़ के सैनिकों का मुकाबला किया, लेकिन हुएर्ता ने पाला बदल लिया और माडेरो को हटा दिया। हुएर्ता ने इसके जबाव में सेना का आकार बढ़ा दिया। देश के सामने अब दूसरी समस्याएँ खड़ी हो गईं। संघीय खजाना खाली हो गया और प्रत्येक गुट अपनी-अपनी मुद्रा जारी करने लगा। महत्वपूर्ण बात यह थी कि हुएर्ता की सरकार को संयुक्त राज्य अमेरिका ने मान्यता नहीं दी थी। 1914 तक, हुएर्ता को इस्तीफा देना पड़ा।

हुएर्ता के पतन के बाद, देश में गृह युद्ध और निरंकुशता का एक और दौर चला, जिसमें चार सरकारों ने जनता की आकांक्षाओं का प्रतिनिधि होने का दावा कर दिया: वेराक्रूज़ में कारांसा, मैक्सिको सिटी में ओब्रेगॉन, रोक गोंज़ालेज़ गार्ज़ा (ज़पाटावादियों के समर्थन से), और ग्वानाजून्तो में विला। उसी वर्ष बाद में, कारांसा संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से क्रान्तिकारी सेनाओं का विजेता सेनापति होकर उभरा। कारांसा ने एक संविधान का प्रारूप कांग्रेस को पेश किया। वैसे, इस संविधान के 1917 के अंतिम संस्करण में मैक्सिको के लोगों को अतिरिक्त अधिकार दिए गए। यह क्रान्ति का फल था - यह जनाकांक्षाओं की अभिव्यक्ति थी जिसमें नागरिक स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का उत्तराधिकार न होने, और विदेशी तथा घरेलू शोषण से सुरक्षा की गारंटी सभी मैक्सिकोवासियों को दी गई थी।

कारांसा ने 1917 मे सविंधान को औपचारिक रूप में स्वीकार कर लिया, और राष्ट्रपति का चुनाव जीत कर 1 मई 1917 को अपने पद की शपथ ली। मैक्सिको में स्थितियाँ फिर विप्लव जैसी थीं: अर्थव्यवस्था गृह युद्ध के वर्षों में चरमरा गई थी, संचार व्यवस्था बुरी तरह से बाधित हो गई थी, और वस्तुओं के अभाव के चलते अंधाधुंध मुद्रास्फीति की हालत पैदा हो गई थी। जमीन और मज़दूरी अभी भी मैक्सिकोवासियों के लिए बुनियादी मुद्दे बन गए थे। किन्तु, इन मुद्दों से निपटने के लिए कारांसा ने संविधान के प्रावधानों की अनदेखी करना ही बेहतर समझा और क्रान्ति के दौरान ली गई ज़मीनों को वापस कर दिया। 1918 में मोरेलोस में लड़ाई जारी थी। उस क्षेत्र के ज़पाटा समर्थकों की शिकायतें अति विशिष्ट थीं, और वे संविधान से भी कुछ अधिक चाहते थे। बहरहाल, कारांसा के

आदमियों ने 10 अप्रैल 1919 को ज़पाटा को मार डाला। 1920 तक मैक्सिको की क्रान्ति का अंत हो चुका था, क्योंकि कारांसा भी खत्म हो चुका था और जनरल ओब्रेगोन ने सत्ता संभाल ली थी।

11.3.2 बोलाविया की क्रान्ति (1952-1964)

महा मंदी के दौर में लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों का बहुत नुकसान हुआ था। बोलाविया भी इसका अपवाद नहीं था। वहाँ 1932-1935 के चाको युद्ध के जो भयंकर परिणाम सामने आए उन्होंने बोलाविया की जनता को स्तब्ध करके रख दिया। यह युद्ध चाको क्षेत्र में पेराग्वे के साथ एक सीमा-विवाद का परिणाम था। युद्ध ने स्थानीय और 'मेस्तीज़ो' किसानों की अधिकांश आबादी को लामबंद कर दिया, और इससे भारी असंतोष और सामाजिक उथल-पुथल पैदा हो गई। यह स्थिति यहाँ तक पहुँच गई कि अभी तक जो वामपंथी निष्प्रभावी थे वे भी समाज को युद्ध में धकेलने वाली राजनीतिक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश बनाने में सफल हो गए। इस बीच अनेक राजनीतिक दल बने, जिनमें तीन समाजवादी दल थे और दो फासीवाद-समर्थक दल। इनमें सर्वाधिक प्रतिभाशाली नेतृत्व राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन (National Revolutionary Movement – MNR) का रहा, जिसने अपनी फासीवादी प्रवृत्ति को छोड़ दिया। दक्षिणपंथी शासकों के हाथों कई वर्षों तक मध्यम वर्ग का शोषण होने के बाद, राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन ने 1952 में शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया।

पाज़ एस्तेनसोरो के राष्ट्रपति काल में जुलाई 1952 में सरकार ने साक्षरता और संपत्ति की अर्हता को हटाकर सभी को मतदान का अधिकार दे दिया। इस प्रकार योग्य मतदाताओं की संख्या बढ़ गई। सरकार ने तेज़ी से कार्रवाई करते हुए सशस्त्र सेनाओं पर भी नियंत्रण कर लिया। उसने पिछले रूढ़िवादी शासनों से जुड़े अनेक अधिकारियों को हटा दिया और सेना के आकार और बजट में भारी कटौती कर दी।

उसके बाद सरकार ने तीन बड़ी टिन कम्पनियों की सभी खानों के राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी। उसके बोलाविया के दो-तिहाई खनन उद्योग को एक अर्ध-स्वायत्त उद्यम को सौंप दिया। बोलावियाई खनन निगम (कोमीबोल) को राज्याधीन खानों के संचालन का जिम्मा दिया गया।

इसके बाद कृषि सुधार की एक दूरगामी प्रक्रिया शुरू हुई। सरकार ने कृषि सुधार कानून लागू कर दिया। इस कानून के तहत ज़बरन मज़दूरी समाप्त हो गई और पारंपरिक जमींदारों के कब्जे की ग्रामीण संपत्ति इंडियन किसानों के हाथ में देने का कार्यक्रम चालू हो गया। केवल कम उत्पादन वाली संपदा का वितरण किया गया। अपेक्षाकृत अधिक उत्पादनशील छोटे और मध्यम आकार के फार्मों को अपनी जमीन का हिस्सा रखने की छूट दी गई, और उन्हें इस बात के लिए प्रोत्साहित किया गया कि वे कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नया पूँजी निवेश करें।

क्रान्ति के पहले वर्षों में खनिकों का सरकार के भीतर खूब दबदबा रहा। इसके पीछे अप्रेल 1952 की लड़ाई में खनिकों की निर्णायक भूमिका थी। खनिकों ने बोलावियाई मज़दूर संघ परिसंघ (सेन्ट्रल ओब्रेरा बोलावियाना - Central Obrera Boliviana – COB) का गठन किया। इस परिसंघ की माँग थी कि आमूल परिवर्तन हो और उसके सदस्यों को सरकार में भागीदारी और फायदे मिले। किसानों का भी सशक्त प्रभाव रहा। अंततः राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का किसानों पर नियंत्रण हो गया।

सीलेस जुआज़ो के राष्ट्रपतित्व काल (1956-60) में, संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक सहायता अपने चरम पर पहुँच गई। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सलाह पर सीलेस जुआज़ो शासन ने राजनीतिक दृष्टि से खतरनाक अनेक उपाय करते हुए मुद्रा स्फीति को कम कर दिया। इनमें मज़दूरी की वृद्धि रोक देना भी शामिल था।

राष्ट्रपति के रूप में पाज़ एस्तेनसोरो की दूसरी पारी (1960-64) में राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन में अंदरूनी टकराव बढ़ गया। पाज़ ने "त्रिकोणीय योजना" को स्वीकृति दे दी। इस योजना कोमीबोल के कार्यों पर मज़दूरों के नियंत्रण को समाप्त करने और टिन खनन उद्योग के पुनर्गठन, मज़दूरों की छंटनी और उनके वेतनों और लाभों में कटौती की माँग की गई थी, जिसका सेन्ट्रल ओब्रेरा बोलावियाना ने विरोध किया। इसके अतिरिक्त, किसान समूहों की प्रतिद्वंद्विता अक्सर खून-खराबे का रूप ले लेती थी जिससे पाज़ की सरकार को और भी कमज़ोर कर दिया।

सरकार ने जो बदलाव किए उनके परिणामस्वरूप देश के सामने गंभीर आर्थिक समस्याएँ खड़ी हो गईं। खानों के राष्ट्रीयकरण का गलत असर हुआ क्योंकि ज़र्जर होते संयंत्रों को आधुनिक बनाने के लिए न तो पर्याप्त तकनीकी विशेषज्ञता थी और न ही पूँजी। क्रान्ति के पहले वर्षों में कृषि उत्पादन में भी गिरावट आई। यद्यपि उत्पादन में कमी का मुख्य कारण ग्रामीण निरंकुशता थी, बाज़ार-अर्थव्यवस्था के लिए उत्पादन करने में किसानों की अयोग्यता और परिवहन के साधनों के अभाव का भी इसमें योगदान रहा। सामाजिक व्यय के कारणों बनी मुद्रा स्फीति ने भी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाया। सरकार के लिए इंडियन किसानों, मज़दूरों, और मध्यम वर्ग का समर्थन जुटाने के राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रयास को उसी की भीतरी फूट ने कमज़ोर कर दिया। 1952 में राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन विभिन्न हितों वाले समूहों का एक व्यापक गठबंधन था। दिवालिया अर्थव्यवस्था ने राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन की भीतरी गुटबाजी को बढ़ा दिया। क्योंकि राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन के अधिकांश कुलीन मध्यम मार्ग अथवा नरमी चाहते थे और वामपंथी आमूल परिवर्तन की माँग कर रहे थे, इसलिए ध्रुवीकरण बढ़ गया और अंततः इसके परिणामस्वरूप 1964 में राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन समाप्त हो गया।

अपने बारह वर्ष के शासन के दौरान, राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन एक लोकतांत्रिक नागरिक सरकार के लिए सुदृढ़ आधार बनने में नाकाम रहा था। बढ़ती गुटबाजी, खुले असंतोष, वैचारिक मतभेद, नीतिगत गलतियों और भ्रष्टाचार ने पार्टी को क़मजोर कर दिया और सुधारों के लिए एक संस्थागत ढाँचा खड़ा करना असंभव हो गया। क्रान्ति का सर्वाधिक लाभ उठाने वाले किसानों ने भी जमकर राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन का समर्थन नहीं किया।

राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन इसलिए कामयाब हुआ था क्योंकि यह देश की प्रमुख राजनीतिक शक्तियों को एकजुट करने में सफल रहा था। इसने खनिकों, सशस्त्र सेनाओं और अधिकांश मध्यम वर्ग और उन किसानों को भी एक सूत्र में बाँध दिया था जो क्रान्ति के बाद उभरने वाला चौथा समूह था। राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन नाकाम भी इसी कारण हुआ – वह इस गठबंधन को कायम नहीं रख पाया।

11.3.3 क्यूबा की क्रान्ति

क्यूबा की क्रान्ति अनेक अर्थों में एक अनूठी घटना थी। इसके केन्द्र में फिदेल कास्त्रो का व्यक्तिगत करिश्मा था। कास्त्रो एक युवा वकील थे जिन्होंने सफल छापामार लड़ाई करके फूलहेंसियो बातीस्ता के सैनिक शासन का उखाड़ फैंका। इन क्रान्तिकारियों का उद्देश्य भूमि सुधार और साम्यवाद के माध्यम से संपत्ति को पुनर्वितरण करना था। 1960 के अंतिम दौर में, राज्य के पास उत्पादन के साधनों का एक अच्छा खासा हिस्सा था। राष्ट्रवाद की भावना के चलते ये क्रान्तिकारी संयुक्त राज्य अमेरिका से दूर समाजवाद की ओर चले गए।

इस प्रकार, क्यूबा में किसी क्रान्तिकारी सिद्धान्त अथवा पार्टी के बिना ही सत्ता हथिया ली गई। बाद में दिसम्बर 1961 में जाकर ही एक क्रान्तिकारी पार्टी के गठन की शुरुआत हुई। पार्टी की पहली कांग्रेस का आयोजन तेरह वर्षों के बाद हुआ।

क्रान्ति के पहले सोलह वर्षों में, कम्युनिस्ट पार्टी ने कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई, बस मज़दूरों, औरतों, छात्रों, किसानों और क्रान्ति के समर्थकों को व्यापक पैमाने पर लामबंद करने पर जोर दिया। 1975 में जब पार्टी ने संस्था का रूप ले लिया, तब इसकी भूमिका बस राज्य और जनसाधारण के संगठनों के कामों में प्रशासन से बाहर रहकर तालमेल बैठाने और उनकी निगरानी करने की थी। कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक सत्ता का ठिकाना बन गया। इस प्रकार, कार्य की दृष्टि से पार्टी, राज्य और सरकार अलग-अलग हो जाते हैं।

क्रान्तिकारियों को विरासत में एक पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मिली थी जिस पर संयुक्त राज्य अमेरिका की पूँजी का नियंत्रण था, और यह अर्थव्यवस्था अतिरिक्त मज़दूरों को काम पर लगाने के लिए पर्याप्त नौकरियों का सृजन करने में अक्षम थी। क्रान्ति के बाद के दो वर्षों में ही मकान के किराये 50 प्रतिशत तक कम हो गए, सबके लिए मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था कर दी गई, सभी मज़दूरों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई, 'कृषि सुधार कानून' के अंतर्गत जमीन का पुनर्वितरण शुरू हो गया, परिवहन को सस्ता कर दिया गया, और शिशु देखभाल केन्द्रों को राज्य की ओर से अनुदान (सब्सिडी) दिया जाने लगा। बैंकिंग, आयात-निर्यात और ऊर्जा जैसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्रों को सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। तीन-चौथाई से अधिक उद्योग, निर्माण और परिवहन भी राज्य के हाथों में था। जल्दी ही स्वास्थ्य की देखभाल भी मुफ्त होने लगी। क्यूबा में भौतिक प्रोत्साहन की गुजांइश नहीं होने के कारण कामगारों को प्रेरित करने के लिए नैतिक प्रोत्साहन का सहारा लिया गया। करिश्माई अधिकारियों ने नैतिक प्रोत्साहनों और जनसाधारण की लामबंदी के बदल पर आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया। 1970 के दशक से राजनीतिक और आर्थिक दोनों ही क्षेत्रों में तार्किक-कानूनी प्राधिकार को अपना लिया गया।

11.3.4 निकारागुआ की क्रान्ति

निकारागुआ में जनरल अनस्तासियो सोमोसा गार्सिया के नेतृत्व में स्थापित तानाशाही केन्द्रीय अमेरिका का राजनीतिक इतिहास की सबसे स्थायी तानाशाही थी। सोमोसा वंश की कामयाबी का प्रमुख कारण अमेरिका-रचित नेशनल गार्ड पर उसका नियंत्रण, निकारागुआ के भीतर सशस्त्र बल पर एकाधिकार रखने वाला एक मिश्रित सेना-पुलिस बल और अमेरिकी समर्थन को निरंतर बनाए रखना था। जब तक अर्थव्यवस्था में विकास की स्थिति बनी रही और पारम्परिक कुलीनों और विपक्षी दलों को लाभ में हिस्सा मिलता रहा, तब तक तो उन्हें सब कुछ स्वीकार्य रहा। 1972 के विनाशकारी भूकंप ने जैसे पूरी ढाँचागत व्यवस्था को ही ठप कर दिया, किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका की मदद से वह जैसे-तैसे बच गई। इससे सोमोसा शासन के प्रति जनता का असंतोष बढ़ गया। सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे (Sandinista National Liberation Front – FSLN) के छापामारों ने अपनी गतिविधियाँ तेज़ कर दीं। 1978 में जब सोमोसा के व्यापारिक सहयोगियों ने निकारागुआ के प्रमुख समाचार पत्र प्रकाशक और विपक्षी नेता कार्लोस फोन्सेका अमाडोर की हत्या कर दी, तो राष्ट्र में विद्रोह और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विक्षोभ की स्थिति पैदा हो गई। लगातार चले जन-विद्रोहों और सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे की ओर से भारी लड़ाई और उसके साथ अन्तर्राष्ट्रीय विरोध ने तानाशाह शासक की मुश्किलों को और बढ़ा दिया।

ओ ए एस के नेतृत्व में 1979 में चली मध्यस्थता की प्रक्रिया तब रुक गई जब राष्ट्रपति सोमोसा ने राष्ट्र में जनमत संग्रह कराने से इन्कार कर दिया और 1981 तक सत्ता में बने रहने की जिद पर अड़ गए। लड़ाई तेज़ हो जाने से निकारागुआ की अर्थव्यवस्था को एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। कृषि और औद्योगिक उत्पादन में जबरदस्त गिरावट आ गई; बेरोज़गारी, मुद्रा स्फीति, प्रतिरक्षा व्यय और पूँजी पलायन बढ़ गया। सरकारी कर्ज़ भी बढ़ गया, जिसका प्रमुख कारण प्रतिरक्षा व्यय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की तमाम वित्तीय संस्थाओं से धीरे-धीरे आर्थिक मदद समाप्त कर देना रहा।

फिर 1 फरवरी 1979 को सैंडिनिस्तास ने राष्ट्रीय देशभक्ति मोर्चा (Frente Patriotico Nacional – FPN) की स्थापना कर ली जिसमें *लॉस डोसे* (*Los Doce*), पी एल आई, और पॉपुलर सोशल क्रिश्चियन पार्टी (Partido Popular Social Cristiano - PPSC) शामिल थी। सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे (FSLN) ने अपना अंतिम अभियान मई महीने में शुरू किया, जब देश के अनेक हिस्सों से नेशनल गार्ड का नियंत्रण समाप्त होने लगा था। सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे ने साहसिक सैनिक और राजनीतिक कार्रवाइयाँ करके एक ही वर्ष में वह स्थिति बना ली कि वह कई विपक्षी गुटों में से एक न रह कर सोमोसा-विरोधी क्रान्ति का अगुआ बन गया। 19 जुलाई 1979 को सैंडिनिस्टा मानागुआ में घुस आए, और इसके साथ ही लैटिन अमेरिकी इतिहास के सबसे लंबे पारिवारिक तानाशाह शासन का अंत हो गया।

एक पाँच-सदस्यीय शासक गुट ने निकारागुआ की राजधानी में घुसकर सत्ता अपने हाथ में ले ली। इनमें *सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे* (FSLN) के डैनिएल होसे ओर्टेगा सावेद्रा, राष्ट्रीय निदेशालय कर राष्ट्रीय देशभक्ति मोर्चा (FPN) के मोइसेस हसन मोरोलेस, सेर्जियो रमीरेस मेर्कार्डो, एम डी एन के अल्फोंसो रोबेलो कालेहास, और 'ला प्रेंसा' के संपादक की विधता, वायलेटा बारियोस डि चमोरा शामिल थे। इस शासक गुट ने राजनीतिक बहुलवाद, मिश्रित आर्थिक व्यवस्था, और एक निर्गुट विदेशी नीति के अपने वादे को दुहराया।

नई सरकार को एक ज़र्जर देश विरासत में मिला, जिसकी अर्थव्यवस्था खराब स्थिति में थी और उस पर लगभग 16 खरब (Billion) अमेरिकी डॉलर का कर्ज था। अधिकांश निकारागुआवासियों को सैंडिनिस्टा की जीत में लगभग सर्वघृणित सोमोसा शासन की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक असमानताओं से मुक्त व्यवस्था कायम करने का अवसर दिखाई दिया।

नई सरकार का पहला अथवा तुरंत लक्ष्य राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का पुनर्गठन था। नई सरकार ने कृषि सुधार कानून को लागू करते हुए सोमोसा परिवार और उनके सहयोगियों के अधिकार वाली सभी ग्रामीण संपत्तियों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसमें निकारागुआ की 20 प्रतिशत से भी अधिक कृषि योग्य भूमि थी। ये खेत नए कृषि सुधार मंत्रालय के तहत राज्य की संपत्ति हो गए। युद्ध के समय भारी पूँजी पलायन से दिवालिया हुई सभी वित्तीय संस्थाओं का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

सैंडिनिस्टास का दूसरा लक्ष्य पुरानी सरकार की दमन और पाशविकता की नीति में बदलाव था। सोमोसा शासन के दौरान अन्याय के आरोपी अधिकांश कैदियों का मुकदमा चलाया गया और गृह मंत्रालय ने कैदियों के साथ क्रूरता पर पाबंदी लगा दी। एमनेस्टी इंटरनेशनल और अन्य मानवाधिकार संगठनों ने निकारागुआ में मानवाधिकारी की स्थिति को बहुत बेहतर पाया।

देश के नए नेताओं का तीसरा प्रमुख लक्ष्य क्रान्ति को सुदृढ़ करने के लिए नई राजनीतिक संस्थाओं की स्थापना करना था। इसके लिए 22 अगस्त 1979 को 'निकारागुआ गणराज्य का मूलभूत विधान' की घोषणा करके संविधान राष्ट्रपतित्व, कांग्रेस और सभी अदालतों को समाप्त कर दिया। 'शासक गुट' आपात् कालीन शक्तियों के अधीन शासन करता रहा। वैसे, राष्ट्रीय सरकारी नीति का निर्धारण सामान्यतया सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे (FSLN) का शासक निकाय, नौ सदस्यीय संयुक्त राष्ट्रीय निदेशालय (Direccion Nacional Conjunto – DNC) करता था। एक सलाहकार नैगम प्रतिनिधि सभा, राज्य परिषद शासक गुट से मिले कानूनों का अनुमोदन करती थी। वैसे, शासक गुट के पास वीटो का अधिकार था और वह अधिकांश बजट पर अपना नियंत्रण रखता था। शासक गुट का सदस्यता इसके प्रारंभिक वर्षों में बदलती गई। 1983 तक, शासक गुट में तीन सदस्य रह गए थे, जिनमें नेतृत्व स्पष्ट रूप में डैनिएल ओर्टेगा के पास था।

क्रान्ति के ठीक बाद, सैंडिनिस्टास के पास देश की सर्वाधिक सुसंगठित और सर्वाधिक अनुभवी सैन्य शक्ति थी। उनके पास एक नई राष्ट्रीय सेना, सैंडिनिस्टा पीपुल्स आर्मी (Ejercito Popular Sandinista – EPS) और एक पुलिस बल, सैंडिनिस्टा पुलिस (Policia Sandinista – PS) थी। सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FSLN) ने जन संगठन खड़े कर लिए, जिनमें राजनीतिक और सैनिक संस्थाओं पर सैंडिनिस्टा की सत्ता को सुदृढ़ करने में सहायक निकारागुआ के सर्वाधिक लोकप्रिय हित समूह शामिल थे। इनमें मज़दूर यूनियनों के प्रतिनिधि (Central Sandinista de Trabajadores – CST), लूइसा अमांडा एस्पिनोसा निकारागुआई महिला समिति (Asociacion de Mujeres Nicaraguenses Luisa Amanda Espinoza – AMNLAE) और कृषकों तथा पशुपालकों का राष्ट्रीय संघ (Union Nacional de Agricultores y Ganaderos – UNAG) थे।

नई सैंडिनिस्टा सरकार का हर किसी ने स्वागत नहीं किया। घरेलू मोर्चे पर, कैरिबियाई तट के जातीय अल्पसंख्यकों ने उन्हें राष्ट्रीय मुख्यधारा में शामिल करने के सैंडिनिस्टा के प्रयासों को खारिज कर दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने उस पर एल सल्वाडोर में छापामारों को हथियार आपूर्ति करने का आरोप लगाते हुए 'कन्ट्रास' कहे जाने वाले प्रति-क्रान्तिकारियों के समूहों को भी समर्थन दे डाला। रोमन कैथोलिक चर्च के बिशपों ने सैंडिनिस्टा की विचारधारा पर भरोसा नहीं रखा, और 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सोमोसा-विरोधी आन्दोलन का समर्थन कर चुकने के बावजूद 1980 के दशक में सैंडिनिस्टा शासन का विरोध किया।

मध्य 1984 में, निर्वाचन कानून पारित कर दिया गया, और चुनाव की तिथि और शर्तें तय कर दी गईं। जुलाई 1984 तक, आठ पार्टियाँ अथवा गठबंधन अपने प्रत्याशी उतारने के इरादे का ऐलान कर चुके थेः सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FSLN), जिसे राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डैनिएल ओर्टेगा थे; लोकतांत्रिक समन्वयक (Coordinadora Democratica – CD) जो मज़दूर संघों, व्यापारिक समूहों, और चार मध्यमार्गी पार्टियों का व्यापक गठबंधन था; और छह अन्य पार्टियाँ - पी एल आई, पी पी एस सी, लोकतांत्रिक रूढ़िवादी दल (Partido Conservador Democratic – PCD), साम्यवादी समाजवादी और मार्क्सवादी-लेनिनवादी लोकप्रिय एक्शन आन्दोलन। 4 नवम्बर 1984 को, लगभग 75 प्रतिशत पंजीकृत मतदाताओं ने मतदान किया। सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे (FSLN) ने 67 प्रतिशत मत, राष्ट्रपति का पद और नेशनल एसेम्बली की छियानबे में से इकसठ सीटें जीत लीं।

डेनिएल ओरटेगा ने राष्ट्रपति के रूप में अपने छह वर्षों की शुरुआत 10 जनवरी 1985 को की। अगले महीने रीगन प्रशासन ने सैंडिनिस्टा शासन पर क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए निकारागुआ के साथ व्यापार पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। इसके जबाव में सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FSLN) सरकार ने नागरिक आजादी खत्म कर दी। चर्च, मीडिया और रूढ़िवादी समाचारपत्र *'ला प्रेंसा'* (*La Prensa*) को सेंसर, या विभिन्न अवधियों के लिए बंद कर दिया गया और सैंडिनिस्टा सरकार अपने अधिकाधिक आर्थिक संसाधनों को आर्थिक विकास से हटाकर 'कन्ट्रास' के विरुद्ध सुरक्षात्मक उपायों में लगाने को बाध्य हो गई।

निकारागुआ के टकराव को समाप्त करने की दिशा में एक और कदम 15 जनवरी 1988 को केन्द्रीय अमेरिकी राष्ट्रपतियों के एक शिखर सम्मेलन में उठाया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रपति डैमिएल आर्टेगा कन्ट्रास के साथ सीधे बातचीत करने, आपात् स्थिति को हटाने, और राष्ट्रीय चुनाव करवाने को सहमत हो गए। मार्च में, सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FSLN) सरकार ने कन्ट्रास के प्रतिनिधियों से भेंट की और युद्ध विराम के एक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। 1988 के मध्य तक, अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने यह माँग कर दी कि सहायता बहाली की एक शर्त के तौर पर सैंडिनिस्टा आर्थिक समायोजन का एक कठोर कार्यक्रम शुरू करें। इस नए आर्थिक कार्यक्रम ने निकारागुआ के

लोगों को और भी मुश्किल में डाल दिया। जब देश दिवालिया होने लगा और आर्थिक तंगी से जूझते सोवियत संघ से आर्थिक मदद मिलनी बंद हो गई तो सैंडिनिस्टा ने आम चुनावों की तारीख आगे करने का फैसला किया जिससे अन्तर्राष्ट्रीय कांग्रेस कन्ट्रास को सभी सहायता बंद करने को मान जाए और यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से उसे आर्थिक मदद भी मिल जाए।

सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FSLN) सरकार ने राजनीतिक स्वतंत्रताओं (अधिकारों) को बहाल कर दिया। निकारागुआ के अनेक लोग यह सोचते थे कि यदि सैंडिनिस्टा के पास सत्ता रही तो देश का आर्थिक संकट और गहरा हो जाएगा और कन्ट्रास के साथ संघर्ष चलता रहेगा। उसके विपरीत, बायलेटा बारियोस डि चमोरो ने अलोकप्रिय सैनिक प्रारूप को समाप्त करने, लोकतंत्र की बहाली करने, और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का वादा करते हुए 25 जनवरी 1990 का चुनाव जीत लिया। सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चे (FSLN) ने विपक्ष की अपनी नई भूमिका को स्वीकार करते हुए 25 अप्रेल 1990 को वायलेटा चमारों और संयुक्त राष्ट्र संगठन गठबंधन (UNO) को सत्ता सौंप दी।

11.4 तुलनात्मक विश्लेषण

सामान्यतया, सफल क्रान्तियाँ (जो कहीं प्रति-क्रान्ति की शिकार नहीं बनतीं) सत्ता के हस्तांतरण, संसाधनों के पुनर्वितरण, बदलाव के संस्थायन, और पुनर्निर्माण अथवा पुनर्संक्रेन्द्रण के कुछ निश्चित चरणों से होकर गुज़रती हैं।

i) **सत्ता का हस्तांतरणः** यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। जब पुराने शासन को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर एक नए शासन को लाना भी होता है। लोग किस प्रकार की सरकार चाहते हैं, इस पर सहमति बनाने की प्रक्रिया संघर्षपूर्ण हो सकती है।

   मैक्सिको में, 1911 में फोरफीरिया डियास की तानाशाही का अंत होने के बाद, दस वर्षों तक सशस्त्र संघर्ष चलता रहा था, और तब जाकर सत्ता मज़बूत हुई थी। बोलिविया में, 1952 में सत्ता संभालने वाला राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन खनिकों और किसानों के साथ अपने गठजोड़ को कायम नहीं रख पाया और बहुत थोड़े समय में दम तोड़ गया। राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन, खनिक और किसान नियंत्रण नहीं कर सके। क्यूबा में, सत्ता का समेकन इसलिए सफल रहा क्योंकि उच्च वर्ग के लोग थोक भाव में संयुक्त राज्य अमेरिका को कूच कर गए। निकारागुआ में, 1979 का बहु-वर्गीय गठबंधन एक वर्ष के भीतर ही खुलने लगा था। सैंडिनिस्टा के समर्थन में जुटाए गए उच्च वर्गीय व्यापारियों ने नेशनल गार्डस के लोगों के साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका के सहारे तख्ता पलट का रुख किया था।

ii) **वर्ग ध्वंस और पुनर्वितरणः** क्रान्ति की सफलता के लिए यह ज़रूरी होता है कि शासक कुलीन वर्ग को समर्थन दे रही वर्चस्वशाली औपनिवेशिक शक्ति को हटाया जाए। लैटिन अमेरिका के अलग अलग देशों में अलग-अलग ढंग से यह काम हुआ है। इसका मतलब यह होता है कि उस बाहरी वर्चस्वशील सत्ता को उस देश के आंतरिक मामलों में सीधी भागीदारी से हाथ धोना पड़ता है। लैटिन अमेरिका के अधिकांश देशों में औपनिवेशिक शक्तियाँ और भूमि संपन्न अभिजात वर्ग एक ही है।

   मैक्सिको में, क्रान्ति ने भूमिधर अभिजात वर्ग और चर्च को विस्थापित कर दिया, जो एक बड़ा भूमिधर था। इसने आयात-निर्यात व्यापार में लगे कुलीन व्यापारी वर्ग को भी कमज़ोर कर दिया, जिससे एक राष्ट्रीय औद्योगिक क्षेत्र का उदय हुआ। बोलाविया में, भूसम्पन्न अभिजातवर्ग और

टिन की खानों पर काबिज़ व्यक्तिगत हित समूहों को विस्थापित कर दिया गया। किन्तु, बोलाविया में क्रान्तिकारी शक्तियों ने कुछ शर्तों के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता को स्वीकार कर लिया। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका को क्रान्ति का निशाना और उपलब्धि बनाना ठीक नहीं समझा। इसी कारण, एक नया सैनिक कुलीनवर्ग पनप गया और क्रान्तिकारी शक्तियों के बीच गठबंधन की हार हो गई। क्यूबा में संयुक्त राज्य अमेरिका का एक मज़बूत ठिकाना था। इसीलिए, वहाँ क्रान्ति का निशाना संयुक्त राज्य अमेरिका और उसकी सेवा करने वाले सैनिक तंत्र को बनाया गया। क्यूबा का राष्ट्रोन्मुख व्यापारी वर्ग अत्यधिक कमजोर था। निकारागुआ में, क्रान्ति के निशाने पर सोमोसा की तानाशाही, उसके नेशनल गार्ड जैसे स्थानीय समर्थक, और उस वंश का हितैषी संयुक्त राज्य अमेरिका रहे। निकारागुआ में कैथोलिक चर्च कम से कम प्रारंभ में तो क्रान्तिकारी गठबंधन से प्रतिबद्ध रहा।

संपत्ति का पुनर्वितरणः क्रान्ति में संपत्ति का पुनर्वितरण इस बात पर निर्भर करता है कि पुनर्वितरण होने लायक संपत्ति है कितनी। क्यूबा क्रान्ति के समय एक सम्पन्न देश था। इसलिए, वहाँ पुनर्वितरण का काम सेवाओं के विस्तार के रूप में हुआ। क्यूबा की लोक स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्थाएँ उस गोलार्द्ध में सर्वोत्तम थीं। बोलाविया और निकारागुआ में, पुनर्वितरण के लिए अपेक्षाकृत न्यूनतम संपत्ति थी।

iii) **संस्थायनः** क्रान्ति के रसायन, अर्थात् उसे संस्था का रूप देने के लिए बिल्कुल नए राजनीतिक समर्थन गुटों और नए संविधानों, कानूनों और व्यवहार-प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। नए समर्थन समूहों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण छतरी संगठन राजनीतिक दल होता है। मैक्सिको में, क्रान्तिकारी राजनीतिक दल 1929 में अस्तित्व में आया, और 1930 और 1940 के दशकों में उसका पुनर्गठन किया गया। उसको संस्थागत क्रान्तिकारी पार्टी (Institutional Revolutionary Party – PRI) का नया नाम दिया गया। बोलाविया का जहाँ तक सम्बंध है, तो वहाँ राष्ट्रीय क्रान्तिकारी आन्दोलन (MNR) को संस्थायन का वाहक माना गया। किन्तु यह पार्टी खनिकों को शामिल करने अथवा उत्तराधिकार के संस्थायन में सफल नहीं हुई। इसलिए, बारह वर्षों बाद यह प्रति-क्रान्ति की शिकार हो गई। क्यूबा में, कम्युनिस्ट पार्टी और क्रान्तिकारी सशस्त्र बल संस्थायन के प्रमुख वाहक थे, जिसकी लगाम फिदेल कास्त्रों के हाथों में थी। राष्ट्र के राजनीतिक महा ढाँचे को जन संगठनों के आधार पर बनाया गया। निकारागुआ में, 1959 में एक छोटे-से विद्रोही गुट के रूप में शुरू होने वाला सैंडिनिस्टा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (FSLN) क्रान्तिकारी जीत के समय सबसे अधिक प्रभावशाली गुट था। सैंडिनिस्टा के नेतृत्व को मज़दूरों, किसानों, स्त्रियों और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले जन संगठनों के सदस्यों का अच्छा समर्थन प्राप्त था।

iv) **पुनर्निर्माण अथवा पुनर्संकेन्द्रणः** सत्ता के और तमाम संयोजनों की तरह क्रान्तियाँ भी अस्थायी होती हैं। संपत्ति और सत्ता की प्रवृत्ति तो पुनर्संकेन्द्रण की है और समाज के निचले तबके के लोगों की ताकत और स्थिति कमज़ोर होने लगती है।

मैक्सिको में, क्रान्तिकारी नेता एक 'नया वर्ग' - आर्थिक और राजनीतिक सत्ताधारी कुलीन वर्ग - बन गए। क्यूबा में, कास्त्रो और उनके समर्थकों के 'कुलीन' वाली हैसियत से बचने के बावजूद, कभी जनता की सेना रही सेना में भी पदों के भेद और विशेषाधिकार घुस आए हैं। फिर भी, सामान्यतया यही समझा जाता है कि जिन देशों में क्रान्तियाँ हो चुकी हैं, वे देश उन देशों की तुलना में अधिक स्थिर होते हैं जहाँ क्रान्ति नहीं हुई है।

लैटिन अमेरिका के आन्दोलन निस्संदेह बहु-वर्गीय प्रकृति के थे। हो सकता है कि इन सभी आन्दोलनों

की परिणति समान रूप से किसी महत्वपूर्ण सामाजिक अथवा राजनीतिक बदलाव में नहीं हुई हो, किन्तु जो बात उन्हें क्रान्तिकारी बनाती हैं, वह है जन साधारण को अपने साथ जोड़ने का उनका ढंग। उत्तर-क्रान्तिकारी कुलीन भी राज्य निर्माता थे, किन्तु उन्होंने पहले के गुटों में बंटे और खंडित समाज के बजाय एक लोक-समाज की रचना की। कुछ इतिहासकारों ने इन क्रान्तियों के लोक और किसानी पक्ष की अवहेलना करने का प्रयास किया है। किन्तु, विशेषकर मैक्सिको के मामले में, यह स्पष्ट है कि वहाँ भारी और हिंसक ग्रामीण विद्रोह हुए थे। सचमुच, यह समान स्पष्ट रूप में नहीं कहा जा सकता कि क्रान्तियाँ विशुद्ध रूप में कृषि क्रान्तियाँ ही थीं। मैक्सिको तक की क्रान्ति में ग़ैर-किसान नेता थे जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। पाँचों विला की उत्तर की जन सेना उन किसान ग्रामीणों से बिल्कुल भिन्न थी जो एमिलियानो ज़पाटा की दक्षिण की सेना के मूलाधार थे।

11.5 सारांश

लैटिन अमेरिका में हुए आन्दोलनों को बहुत अलग, ढीले-ढाले ढंग से परिभाषित किया जाता है, और उन्हें हिंसा, शासन परिवर्तन, सामाजिक बदलाव और यहाँ तक कि सैनिक अधिनायकवादी शासन से भी जोड़ दिया जाता है। इस इकाई में लैटिन अमेरिका के अधिक सफल क्रान्तिकारी आन्दोलनों का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करते हुए उनके कारणों, मुख्य विशेषताओं और उनकी प्रगति के चरणों का विवेचन किया गया है। लैटिन अमेरिका में राजनीति में कम भागीदारी, और जन साधारण तथा कुलीनों के बीच अधिक अंतर, और यथास्थिति बनाए रखने के कुलीनों के प्रयासों के चलते हमेशा ही जन असंतोष की स्थिति बनती रही है। और, संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्षेत्र में एक प्रभावशाली शक्ति बनकर उभरा है।

11.6 अभ्यास प्रश्न

1) आप एक क्रान्तिकारी आन्दोलन और अन्य सामाजिक आन्दोलनों में किस प्रकार भेद करेंगे? लैटिन अमेरिका से उदाहरण देते हुए यह स्पष्ट कीजिए कि आपकी दृष्टि में किसे अपेक्षाकृत 'सफल क्रान्ति' कहा जा सकता है?

2) लैटिन अमेरिका में क्रान्तिकारी आन्दोलन किन कारणों से हुए?

3) आप बोलाविया की क्रान्ति को कहाँ तक सफल मानते हैं?

4) मैक्सिको की क्रान्ति (1911) और क्यूबा की क्रान्ति (1959) जिन चरणों से गुज़रीं उनमें क्या समानताएँ थीं?

5) निकारागुआ की सैंडिनिस्टा क्रान्ति का संक्षिप्त विवरण देते हुए इसकी सीमित सफलता की व्याख्या कीजिए।